

FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

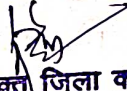
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... आति जिला कलक्टर ...मुकाम... नीमकाथाना

...सलीम खान...बनाम... नाथल तहसीलदार

किस्म मुकदमा... अपील ...नम्बर... 25 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/4/22	<p>रिपोर्ट लखिवा होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपर अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विद्द रेव्हो जारी होकर पञ्चवली दिनांक 25/4/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर) </p> <p>25/4/22 पञ्चवली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपर। रेव्हो कि और से रीडर नाथल तहसीलदार नीमकाथाना उपर। खखल वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने खखल वकील अपीलान्टने खवाया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि खण्ड नं० 2174 रकबा 1.48 हे में से 0.045 हे भूमि पर दीवार लगाकर मकान व बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण नही किया गया है। पञ्चवली द्वाारा जांच कि रजिस्टर व डेवलाप के कारण - जलत रिपोर्ट पेश कि गई है। पञ्चवली द्वाारा अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण कि गई भूमि का नाप भी नही लिखा है। अपीलान्ट अपीलान्ट द्वारा अधिनल्य न्यायालय में जाबाब में देलावेज कर पेश किये गये थे उनका निर्णय में कोई उल्लेख नही किया गया है। खखल प्रकार जो निर्णय पारित किया गया है जो न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण पारित आदेश निरस्तनीय है।</p>	



(अनिल कुमार)
 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
 नीमकाथाना (सीकर)



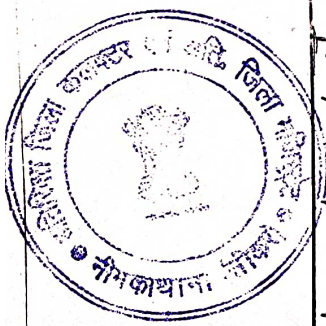
नाथल तहसीलदार
 नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुकम

अपीलान्ट द्वारा कोई मया निर्माण नहीं किया गया है। जो मकान बना हुआ है जो लगभग 60-70 वर्ष पुराना है। तथा मकान में बिजली कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट के मकानों के चारों ओर पूरी आबादी बनी हुई है वर्ष 2022 में सर्वेक्षण विधेयक 23-3-2022 में राजस्थान विधान सभा में पारित किया गया है जिसमें यह भी स्पष्ट किया है कि नदी नालों व पानी के खराब होना व मन्दिर माफी की जमीन को छोड़कर अन्य बनी हुई कालोनी व आबादी में 31-12-2021 तक विकसित हो चुकी कालोनी के पट्टे दिये जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बैंच ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के अन्तर्गत व्याख्या की है कि निजि अचल सम्पत्ति पर लिमिटेशन परिलीमा की वैधानिक अवधि 12 साल है। जबकि सरकारी अचल सम्पत्ति के मामले में 30 वर्ष है। चारागाह भूमि में कमीन ले जो मकान बनाये हुए हैं जिनका दिनांक 28-1-2011 के निष्पत्ति के आदेश अनुसार चारागाह में खले व्यक्तियों के पट्टे बनाने सम्बन्धित राज. सरकार व राज्य मण्डल अजमेर की गार्ड लाइन के अनुसार चारागाह में बनी आबादी होना के आवासीय मकानों को वहाँ से नहीं हटाकर वहाँ के पट्टे जारी किये जावेंगे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2022 को कपास्त फलामा जावें।

रेव्यू द्वारा अधील से सम्बन्धित मूल पत्रावली पेश कि गई। जो शारिह पत्रावली की गई।

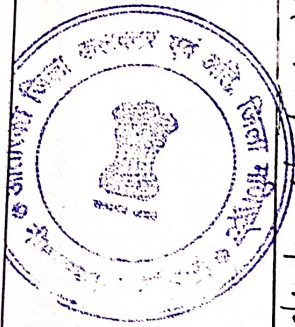
चकील अपीलान्ट की बहस पर पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पत्रवारी हल्का यौग द्वारा



(अनिल कुमार)
 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
 एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
 न्यायकक्ष (सीकर)

जो धारा 91 C.R.A.C कि रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भूमि खण्ड नं० 2774 रकबा 1.48 हेक्टेयर चारागाह में इपीलान्ट द्वारा 0.045 हेक्टेयर अतिक्रमण करना बताया है। इपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नोटिस का जवाब व इलाज पेश किए जो पञ्चवली में शामिल हैं परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। रिपोर्ट जो पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई उसके अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नग्गा बनाया है उसमें माप नहीं लिया गया है। एवं ना ही अतिक्रमण कहा व कितने रकबे पर कर रखा है वो भी नजरी नग्गा में नहीं है। तथा ना ही चारों तरफ का माप अंकित कर रखा है। इस प्रकार इपील इपीलान्ट ने जो तथ्य इपील में अंकित किये हैं वो साबित होते हैं। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो धारा 91 कि रिपोर्ट पेश कि गई है जो माप पर जाकर तैयार नहीं कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट वास्तविक तथ्यों के विपरीत पेश कि गई है। जिसमें अतिक्रमण रकबे की डिशाओ का माप जोख भी नहीं लिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21-3-2022 को जो निर्णय पारित किया गया है उससे पूर्व वास्तविक तथ्यों की जांच किये बिना ही किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इस प्रकार इपील इपीलान्ट द्वारा इपील में जो तथ्य अंकित किये हैं उनकी पुष्टि होती है। तथा प्रस्तुत इपील को खल मिलता है। इस आधार पर इपील इपीलान्ट साबित होने के कारण हकीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर इपील इपीलान्ट साबित होने से हकीकार की जाती है। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-22 अमान्य किया जाता है। इपील इपीलान्ट न्यायालय द्वारा नीमकाधाना को इस आदेश



(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला जलकर
एवं अति. जिला सप्लायर
नीमकाधाना (सीकर)

साथ रिमाण्ड की जाती है कि अतिक्रमिit रखे
की मौके पर जाकर रिपोर्ट मौका फर्द मय
नजरी नम्बरा जिसमें चारो दिशाको का लदी
जाप जोष लित्वा जाकर, कपीलान्ट को
दुनवाई हेतु प्रथित कवर एवं उखुत -
ददतावेज का कवलोकन कर गुणाकगुण के
आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।
पालना हेतु तहसीलदार नीमकायाना को
तहरीर जारी की जाये। पत्रावली फेसल शुभ्रा
होकर नम्बर से कम होकर साकिड फुटर हो।




(अनिल कुमार)
(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला नजिर
नीमकायाना (सिबेर)